



इतिहास में तीसरा ही मौका

अब जब शी ने भी वह ताकत हासिल कर ली है तो सवाल उठना लाजिमी है कि वह इस ताकत का कैसा इस्तेमाल करने वाले हैं। इस दूसरे लक्ष्य को हासिल करने की चीनी नेतृत्व की बेकरारी ही है जो दुनिया के तमाम बड़े देशों की चिंता का कारण बनी हुई है।

मनोज शाह।।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के छठे प्लेनरी सेशन में पार्टी के सौ साल के इतिहास से संबंधित दस्तावेज पारित हुआ। इसे शी के राष्ट्रपति के रूप में अगले कार्यकाल की तैयारी भी माना जा रहा है। उन्हें माओ से भी अधिक ताकतवर माना जा रहा है। यह बात गौर करने लायक है कि अब तक के इतिहास में यह तीसरा ही मौका है, जब पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया। पहली बार 1945 में माओत्से तुंग के नेतृत्व में और दूसरी बार 1981 में तंग श्याओ फंग की अगुआई में पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया था।

ध्यान रहे पार्टी से पारित इस प्रस्ताव के बाद ही माओ के नेतृत्व को वह मजबूती मिली, जिसकी बदौलत 1949 में वह पीपल्स

रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर देश को समाजवादी रास्ते पर ले जा सके। ऐसे ही तंग श्याओ फंग अंगर माओ के नेतृत्व में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान की गई गलतियों को रेखांकित करते हुए देश में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात कर सके, तो उसके पीछे 1981 में पारित इस प्रस्ताव से मिली ताकत की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब जब शी ने भी वह ताकत हासिल कर ली है तो सवाल उठना लाजिमी है कि वह इस ताकत का कैसा इस्तेमाल करने वाले हैं।

जवाब का कुछ संकेत पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई इस बात से मिल जाता कि यह प्रस्ताव दूसरे शतकीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। ध्यान रहे चीनी



कम्युनिस्ट पार्टी ने जो दो शतकीय लक्ष्य तय कर रखे हैं, उनमें पहला है 2021 तक सामान्य रूप में समृद्ध समाज (मॉडरेटली प्रॉस्पेरस सोसायटी) बनना और दूसरा 2049 तक पूर्ण विकसित, अमीर और ताकतवर देश बनना। इस दूसरे लक्ष्य को हासिल करने की चीनी नेतृत्व की बेकरारी ही है जो दुनिया के तमाम बड़े देशों की चिंता का कारण बनी हुई है।

चूँकि मामला अपने समाज को समृद्ध बनाने भर का नहीं, पूर्ण विकसित, अमीर और ताकतवर देश का रूतबा पाने का है, इसलिए स्वाभाविक ही पिछले कुछ समय से चीन की अंतरराष्ट्रीय नीति में एक तरह की आक्रामकता झलकने लगी है। चाहे भारत

के साथ सीमा विवाद का मसला हो या हांगकांग में लोगों के लोकतांत्रिक प्रतिरोध को दबाने का, चाहे साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीपों के जरिए अपने दावों को ठोस रूप देने की कोशिशों का हो या फिर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में अपनाई जाने वाली रणनीति का— हर जगह उसकी यह आक्रामकता अन्य पक्षों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही है। यही वजह है कि दुनिया में एक नई तरह की गोलबंदी बनने लगी है, जिसे कुछ प्रेक्षक शीत युद्ध के एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि 21वीं सदी की दूसरी चौथाई में दुनिया का स्वरूप काफी हद तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर की इन गतिविधियों के भविष्य पर निर्भर करेगा।

छुटकारा

अशोक वोहरा।
वह छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगा। मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा से उसकी जान निकल गई। उसके बाद भी चींटियों ने उसे नहीं छोड़ा और उसका नर्म मांस नोच-नोचकर खा गई। कुछ ही देर बाद वहां सांप का अस्थि पंजर पड़ा था। इसीलिए कहते हैं कि किसी को छोटा समझकर उस पर बेवजह रोब नहीं जमाना चाहिए। बहुत सारे छोटे मिलकर बड़ी शक्ति बन जाते हैं। एक बार एक मुर्गा भोजन की तलाश कर रहा था। भोजन तलाश करने के दौरान ही एक कूड़े के ढेर में उसे एक बड़ा सा हीर मिले। उस हीरे को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने उसे चोंच में भर कर तोड़ना चाहा, परंतु भला हीरा कैसे टूटा।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

नई औद्योगिक नीति

80 के दशक के मध्य में सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई। भारत से पांच साल पहले। इस तरह से बांग्लादेश में एक झटके में 'लाइसेंस राज' का खात्मा हुआ। 80 के दशक के आखिर तक व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण हुआ। पहले जहां देश में जरूरत की चीजें बनाने पर ध्यान था, उस नीति को छोड़ दिया गया। सरकारी कंपनियों का अर्थव्यवस्था में दबदबा था। लेकिन समय के साथ सरकार ने ग्रामीण समुदाय और निजी कंपनियों की उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया। सच कहूं तो ये बदलाव आसान नहीं रहे। इन्हें सहज मानना बांग्लादेश के मुश्किल राजनीतिक सफर के साथ नाइंसाफी होगी। हमारा देश क्रूर राजनीतिक हत्याओं का गवाह बना। उसने सैन्य तानाशाही देखी और बगावत करके लोकतंत्र हासिल किया।

मेरा बांग्लादेश से गहरा और निजी रिश्ता है। मेरी उम्र मेरे देश से अधिक है। इस देश के जन्म में मेरे माता-पिता, सास-ससुर और मेरे परिवार के कई लोगों की भूमिका रही है। वे पहली पीढ़ी के राष्ट्र निर्माता रहे। उन्होंने हमें एक आजाद मुल्क दिया, जिसके सामने असीम संभावनाएं थीं। 50 साल पूरे करने के बाद मन में यही सवाल आता है कि बांग्लादेश के आने वाले 50 साल कैसे होंगे? इतना तो तय है कि ये आसान नहीं होंगे, लेकिन इतिहास साक्षी है कि जो भी चुनौतियां आएंगी, बांग्लादेश उनसे पूरी ताकत से निपटेगा।

अभी सवाल यह है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन पर बीजेपी ने पूरे राज्य में जो माहौल बनाया, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर उन आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो करोड़ों हिंदुओं के मन में लंबे समय से पल रही थी।

प्रवासी हैं हीरो

जुनैद के अहमद।।

बांग्लादेश को आजाद हुए 16 दिसंबर को 50 साल हो गए। जो देश कभी अंतरराष्ट्रीय मदद के भरोसे रहता था, वह इतने कम समय में मध्यम आय वाला मुल्क बन जाएगा, ऐसा हममें से शायद ही किसी ने सोचा हो। एक दशक से भी ज्यादा वक्त से बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 6 प्रतिशत बनी हुई है। शिशु जन्म दर 7 से नाटकीय ढंग से गिरकर 2.03 पर आ गई है। नवजात और शिशु मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। शिक्षा के मामले में लड़के-लड़कियों में फासला नहीं रह गया है। आपदा प्रबंधन में भी हम वैश्विक ताकत बन गए हैं। और हां, हमने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता है। वह भी अपने बड़े पड़ोसी को हराकर! 50 बरसों में विकास को लेकर हमने एक जादू किया है। इस जादू के लिए जो रास्ता चुना गया, वह अनोखा है, बिल्कुल बांग्लादेशी। आखिर हम ये मुकाम हासिल कैसे कर पाए?

इतिहास, मौका और सरकार की होशियारी। ये बांग्लादेश की कामयाबी की बुनियाद हैं। 70 के दशक की शुरुआत में युद्ध और तबाही मचाने वाले तूफान से रिकवरी के साथ हमारा इतिहास शुरू हुआ। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर पहल हुई, जिसमें गैर-सरकारी तंत्र ने बड़ी भूमिका निभाई। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में



लोगों ने तकदीर संवारने का जिम्मा अपने हाथों में लिया। इसी पहल ने आगे चलकर बांग्लादेश में ताकतवर एनजीओ आंदोलन का रूप ले लिया। इस रिकवरी के असल नायक विदेश में काम करने वाले वर्कर्स थे। जो अपनी कमाई गांवों में रहने वाले अपने परिवार के पास भेजते रहे। इस रिकवरी के लिए हमें तकदीर की मदद और मौके की दरकार भी थी। तेल उत्पादक देशों (ओपेक) की अर्थव्यवस्था में जो तेजी आई, उससे वहां बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला। उन वर्कर्स का भेजा गया पैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगा, उनके घर की औरतों के जरिये। इन औरतों के खर्च करने का तरीका भी अलग था। उन्होंने उसका इस्तेमाल बच्चों को शिक्षित और हुनरमंद बनाने के लिए किया। इससे महिला सशक्तीकरण की भी शुरुआत हुई, जो बांग्लादेश के विकास की एक और अनोखी कहानी है। ग्रामीण

अर्थव्यवस्था में इस तरह से जो पैसा लगा, वह सरकारी योजनाओं से अधिक फायदेमंद साबित हुआ। गैर-सरकारी संस्थानों की पहल और इस निवेश ने सामुदायिक पहल को बढ़ावा दिया। लोगों में पहले से उद्यमशीलता थी। ये लोग दूसरी जगहों से आकर इस उपजाऊ क्षेत्र में बसे और लगातार आने वाली आपदाओं से जूझना और उबरना सीखा। तब तक वजूद बनाए रखने के लिए उन्होंने जो तरीके आजमाए, वही उसके बाद राष्ट्र निर्माण के काम आए। इतिहास ने हमारे सामने जो अवसर पेश किए, उसे लेकर सरकारों का रवैया भी सही रहा। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे, जिन्होंने कर्ज, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था का समर्थन किया होगा, जैसा बांग्लादेश में हुआ। सरकार ने 70 के दशक के आखिर में प्रवासियों की ओर से भेजे जाने वाले पैसों को देखते हुए फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफॉर्म (विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार) किए। इस तरह से उसने इसे लेकर ब्लैक मार्केट पर रोक लगाई।

गांवों में प्रवासियों की ओर से भेजी जानी वाली रकम, सामुदायिक स्तर पर सेवाएं देने के तंत्र के उभार और सशक्त एक्सचेंज रेट रिफॉर्म ने शुरुआती दौर में देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। फिर सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार किए। इससे किसानों को बाजार की ताकतों का फायदा उठाने का मौका मिला।

अष्टयोग-5091									
	6	5	4	3	1				
2	39	29		26					
		7	1	2	4				
4	30	25	34						
	2	3		5	6				
6	30	39	35	3					
	5		6	7					

अपना ब्लॉग

सरकारें फायदा उठाती रहीं

मोहन। मौके बनते रहे और सरकारें उसका फायदा उठाती रहीं। 80 के दशक में एक कोरियाई कंपनी बांग्लादेश में दाखिल हुई। किस्मत की ही बात है कि इस कंपनी ने बांग्लादेश को वैश्विक बाजार के लिए गारमेंट बनाना सिखाया। बांग्लादेश की एक कंपनी ने जो पहल की थी, सरकार की सहायता से उसे व्यापक फलक मिला। सरकार की पहल से सभी गारमेंट एक्सपोर्टर्स को बिना किसी टैक्स के आयातित कच्चा माल मिलने लगा। यह काम बॉन्डेड वेयरहाउस सिस्टम के जरिये किया गया। बांग्लादेश ने शुरू में निर्यात के लिए अलग से जोन नहीं बनाए। इसके बजाय उसने वेयरहाउस सिस्टम का लाभ देश में कहीं के भी गारमेंट एक्सपोर्टर्स को दिया। इसलिए वे अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी फैक्ट्री लगा पाए। इससे इन कंपनियों को लागत कम रखने में मदद मिली। आज बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है। इस उद्योग से वहां के बड़े पैमाने पर युवा महिलाओं को रोजगार मिला है। कामगारों में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ी है।

